भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-903

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बिहार में विद्युतीकरण

903. श्री तारिक अनवर:

श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कटिहार जिले सहित बिहार में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण हेतु कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) उक्त राज्य में कितने गांवों और घरों तक अभी भी पूर्ण विद्युतीकरण होना बाकी है;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइनों और सबस्टेशनों जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पर्याप्तता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को ग्रामीण बिहार में बार-बार बिजली कटौती या कम वोल्टेज की रिपोर्ट मिली है;

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण वितरण अवसंरचना को मजबूत करने और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार के पास कटिहार जिले सहित बिहार में 'सौभाग्य' और 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) जैसी योजनाओं के लक्ष्यों और वास्तविक लाभार्थियों के आंकड़े है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, अत: सभी उपभोक्ताओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर, विद्युत लाइन और सबस्टेशन जैसी अवसंरचना की उपलब्धता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने सहित विद्युत की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार/विद्युत वितरण यूटिलिटी की है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना की उचित उपलब्धता और पर्याप्तता है। इसके अलावा, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार के

ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पावर आउटेज या लगातार कम वोल्टेज की कोई बड़ी समस्या नहीं है। राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) के माध्यम से उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की दैनिक औसत अवधि 22.22 घंटे थी।

भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सम्पूरित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें बिहार राज्य के 2,906 गांव और कटिहार जिले के 934 गांव शामिल हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के तहत और उसके बाद सौभाग्य के तहत दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूरा हो गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान बिहार राज्य में 32,59,041 घरों सहित कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे भी मदद कर रही है। इसके अलावा, स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान) के तहत विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिह्नित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी घरों के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के कार्य को मंज़ूरी दी गई है। अब तक, बिहार राज्य में 42,621 घरों के विद्युतीकरण के लिए 301 करोड़ रुपये सहित 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,521 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

(ङ) : भारत सरकार ने विभिन्न स्कीमों जैसे डीडीयूजीजेवाई, जहां सभी गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी; (ख) आईपीडी, जहां शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने हेतु विद्युत वितरण में एक प्रमुख उपाय के रूप में इसकी शुरूआत की गई और (ग) घरों के विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य के तहत निधि के आवंटन के माध्यम से वितरण संस्थाओं द्वारा वितरण अवसंरचना के उन्नयन और निर्माण की सुविधा प्रदान की है। देश की वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कुल मिलाकर 1.85 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। यह स्कीम नेटवर्क सुदृढ़ीकरण और प्रणाली स्वचालन सहित वितरण नेटवर्क के उन्नयन में परिणामोन्मुखी निवेश के माध्यम से वितरण क्षेत्र में तकनीकी और

वाणिज्यिक नुकसान में सुधार पर केंद्रित है। इस स्कीम के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिहार राज्य के लिए 12,581 करोड़ रुपये और कटिहार जिले के लिए 278 करोड़ रुपये शामिल हैं। स्वीकृत कार्यों में सबस्टेशन/ वितरण ट्रांसफार्मर का निर्माण/उन्नयन, कृषि फीडर का पृथक्करण, कंडक्टरों का उन्नयन, घरेलू विद्युतीकरण कार्य आदि शामिल हैं।

(च) : बिहार के कटिहार जिले में स्कीमवार विद्युतीकरण की स्थिति नीचे दी गई है:

डीडीयूजीजेवाई	2,13,906 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों का विद्युतीकरण
सौभाग्य	3,47,597 घरों का विद्युतीकरण

****